Need for speedy disposal of cases, specially pertaining to women, pending in various courts

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): महोदय, आज देश भरा में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 29 लाख से अधिक मामले लम्बित हैं तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में तो इनकी संख्या 70 लाख के लगभग है। ऐसे में फास्ट ट्रैक अदालतों का महत्व काफी बढ़ जाता है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे शीघ्र निर्णय दें। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामलों में तो शीघ्र न्याय का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि पीड़ित महिलाएं न्याय में होने वाले विलम्ब तथा बचाव पक्ष द्वारा विभिन्न प्रकार से धमकाए जाने के कारण टूट जाती हैं। देश में बलात्कार के मामलों को निपटाने में औसत समय 12-13 वर्ष है। विलम्ब से मिलने वाले न्याय का महत्व यूं भी नगण्य हो जाता है। वर्षों में होने वाले न्याय का ही परिणाम है कि तीन-चौथाई मामलों में बलात्कारी बच निकलते हैं। देखा यह गया है कि विदेशी महिलाओं से बलात्कार के कुछ मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा फैसला 21 और 22 दिन में दे दिया गया है। फिर भारतीय महिलाओं के मामले में शीघ्र न्याय क्यों नहीं हो सकता है? बलात्कार के लगभग 57 हजार मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह फास्ट ट्रैक अदालतों को यह परामर्श दे कि वह पीड़ितों को न्याय देने में शीघ्रता करें और विशेष रूप से महिलाओं के मामलों में तो वह अपने ऐतिहासिक निर्णयों को अवश्य दोहराएं।

Request for Central Assistance for Low Price Rice Scheme in Tamil Nadu

SHRI K.P.K. KUMARAN (Tamil Nandu): Sir, the Rs. 2/- per kg rice scheme introduced by the State Government of Tamil Nadu has received a hearty welcome from one and all. The overwhelming success of the scheme has caused ripples in the neighbouring States, and even in far-off States, similar waves has begun to sweep. Every family below the poverty line in these States is yearning for such a scheme to knock at their doors also. Under these circumstances, the demand that the Union Government should make some arrangement in this direction has gathered momentum. The Government of India should come forward to offer a hefty subsidy by way of bearing a part of the financial burden that may soon turn to be unbearable by the slender shoulders of the States. When a question to this effect was put to the Union Minister for Agriculture and Food during his visit to Chennai on the Independence Day, his reply was not sharp enough. He has said that since this is a State subject, the Central Cabinet has to take policy decision first, and so far it has not applied its mind in this regard. The poeple expect a speedy decision in this matter because it has direct relevance with the day-to-day life of the poor people who are leading a hand-to-mouth existence.